

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 25 फरवरी 2025 मंगलवार

सम्पादकीय

राजनीति में विदेशी हाथ

भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर यू.एस.एड या यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट के माध्यम से 21 मिलियन डालर यानी 182 करोड़ रुपए आने की सूचना ने पूरे देश में खलबली पैदा की है। द्रुम्य प्रशासन के अंदर नया-निर्मित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे यानी सरकारी दक्षता विभाग ने उसकी जानकारी देते हुए सूची जारी की। आरंभ में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे रोकने की घोषणा की और कहा कि भारत के पास स्वयं काफी रुपया है तो हम क्यों दें। उस समय ऐसा लगा माना भारत द्वारा अमरीकी सामग्रियों पर लगने वाले आयात शुल्क के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने मिथामी और उसके बाद वाशिंगटन डी.सी. के आयोगनों में कहा कि हमें भारत में मतदान बढ़ाने पर 21 मिलियन खर्च करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे लगता है कि वे किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा।

व्योक्ति जब हम सुनते हैं कि रूस ने हमारे देश में 2 डालर का खर्च किया है तो यह हमारे लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। भारत सरकार की ओर से सूचना है कि जानकारीयों के आधार पर जांच आरंभ हो गई है। हमारे देश की समस्या है कि प्रह्र ानमन्त्री नरेंद्र मोदी की केंद्र व भाजपा की राज्य सरकारों के रहते जब भी ऐसी खबर आती है तो सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रभाव रखने वाला बड़ा वर्ग इसे गलत साबित करने पर तुल जाता है।अमरीकी राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे पास भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप को साबित करने के लिए सटीक प्रमाण नहीं हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना की जा सकती है। डोजे द्वारा यू.एस.एड की जारी सूची में 15 तरह के कार्यक्रम के लिए धन देने की बात है। इन्में एक दुनिया भर में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढीकरण के लिए 48.6 करोड़ डालर यानी 4200 करोड़ का अनुदान था। इसी में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। बंगलादेश को मिलने वाले 251 करोड़ रुपए बंगलादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए दिए जा रहे थे। विश्व में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढीकरण की आवश्यकता अमरीकी प्रशासन को क्यों महसूस हुई? बंगलादेश में राजनीतिक सुधारों के लिए अमरीकी सहायता राशि की जरूरत क्यों थी?

सच है कि सन् 2012 में भारत के चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ पत्र. म्यू.यू. यानी सभमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरेशी ने इन आरोपों और समाचारों को निराधार बताया है कि आई.एफ.एस.सी. से धन आयोग को स्थानांतरित हुआ था। कहीं नहीं कहा गया है कि इसने सीधे चुनाव आयोग को पैसा दिया। इस एजेंसी को यू. एस.एड से धन मिलता था और इसका जार्ज सोरोस की ओपन सोसायटी फाऊंडेशन के साथ संबंध है। ऐसी संस्थाएं किसी माध्यम से अपनी भूमिका को वैधानिकता का आधार देने की दु ष्टि से समझौते करती हैं और फिर अपने अनुसार कार्य करती हैं। पथान रक्षिपू 2012 में महत्वपूर्ण गुजरात विधानसभा चुनाव था तथा उसके पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का। 2013 में पहले कर्नाटक उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। भारतीय चुनावों और राजनीति में विदेशी भूमिका की बात पहली बार नहीं आई है। नरेंद्र मोदी सरकार गठित होने के बाद से इसका चित्र और व्यवहार बदला है किंतु हमारे देश में यह बीमारी लंबे समय से है। जब देश के नेता नौकरशाही, बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि छोटे-छोटे लाभ के लिए खिलौना बनने को तैयार हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है।

शीतयुद्ध काल में सोवियत संघ और अमरीका के बीच प्रतिस्पर्धा थी। दोनों अपने प्रभाव के लिए हस्तक्षेप करते थे। भारत ने 1967, 77, 80 के चुनाव में विदेशी भूमिका की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सोवियत संघ के बिघटन के बाद मित्राधिपन पेपर नाम से ऐनी ज्ञानकारियां आईं जिनसे पढ़ने वाले भीचक्के रह गए थे। भारत में अमरीका के राजदूत रह चुके डेनियल मोयनिहान ने पुस्तक ‘ए जेंजरस प्लेस’ में लिखा है कि भारत में कम्युनिस्टों के विस्तार को रोकने के लिए अमरीका ने भारतीय नेताओं को धम दिया। सन् 1946 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संदेह बढ़ा। 2019 में दोबारा उनके सत्ता में लौटने के बाद अलग तरह के स्वरूपों में अंदोलन हुए जिसेहिहि हस्तक्षेप की बातों भारत के अलावा दूसरे देशों और ताइवान द्वारा भी कही जा रही हैं। विश्व के अनेक देशों की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में विदेशी शक्तियों और संस्थाओं की भूमिका सामने आती रही है। माइक्रोसाफ्ट ने डीपकॉक और ए.आई. के माध्यम से भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिशों पर चेतावनी दी थी। जांच रिपोर्ट में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय प्रतिभावित होतें हों तो मले उन्हे सार्वजनिक न किया जाए किंतु भविष्य में ऐसी खतरनाक भूमिकाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाते चाहिए।

सियासी पापों पर कैसे लगाये कानून की लगाम

—कमलेश पाण्डेय—

भारत की संसदीय राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां राजनीतिक दलों और निर्वाचित जगप्रतिनिधियों को प्राप्त बेहिस्साव अधिकार के दुरुपयोग की जिस तरह की दुनियावी खबरें मिल रही हैं, उससे फस-विषफस दोनों की सियासी भूमिका संदेह के घेरे में है। सुलगता सवाल है कि जब राजनीतिक दलों और उनके द्वारा ही राष्ट्रीयता विरोध ि कार्रवाई की जाएगी, राष्ट्रवाद की अवधारणा को मुंह दिढाते हुए जनविरोधी फंसले लिए जाएंगे और कानून बनाए जाएंगे तो फिर इसकी निष्पक्ष जांच कौन करेगा?

चूंकि भारत में जिन दलित, आदिवासी और पिछड़े मतदाताओं का बहुमत है, उनका कानूनी शिक्षा व राजनीतिक साक्षरता उस स्तर की नहीं है, जो किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। इसलिए उन्हें आख्यान और सामंजस्यवादी जैसे मुद्दों पर सियासी सप्रसूय द्वारा बरगलया जाता है और जनविरोधी—राष्ट्रविरोधी कुकृत्य सनवारित किये जाते हैं। इसलिए प्रबुद्ध सवितल ससाइटी के अजन्मा बदलते कौ की मांग है, अपना दबलते को पुनः गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता।

सच कहें तो जैसे मंगल शासक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दलचंचक को नहीं समझ गए और अंग्रेजों के हथौा अनौी सत्ता गंव दी, कुछ उसी तरह की भूल हमारी निर्वाचित सरकारें एके—दूसरे दल को दबाने के लिए कर रही हैं। कोई दल अमेरिका के हाथ में खेल रहा है, तो कोई दल चीन के हाथ में। कोई पार्टी अरब मुल्कों के प्रभाव में है तो कोई पार्टी यूरोपीय देशों के प्रभाव में। यह अनुचित है और इससे बचने का एक मान रास्ता है कि हमलोग आओं कानून—कानून खेलें वाली प्रवृत्ति से बचें।

बेहतर तो यही होगा कि जैसे पूरे देश में एक समान नागरिक पर नुद है, उसी तरह से हरके मुद है, उससे एक समान कानून नुद है। इसमें जाति, भाषा, क्षेत्र, सम्प्रदाय, लिंग अथवा वर्ग मूलतः जाति के नजरिए से कोई विभिन्ता पैदा नहीं की जाए और इस मामले में ब्रितानी नीतियों का दू कीपी समझ जाने वाले हमारे साक्षिकान में अपेक्षित संशोधन किए जाए। अन्यथा तर्क पर कुतर्क भारी पड़ेगा। लोकतंत्र महज भीड़तंत्र बनकर रह जाएगा। इसे सभ्य बनाने में तब्दील करना दियवस्य बन

ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि बहुमत के जुगाड़ में राजनीतिक दल जो कुछ भी फंसले लिए गए हैं या लिए जाते हैं, या लिए जाने वाले हैं उससे साफ दृष्टिगोचर हो रहा है



जायेगा।

अमूनन, चुनावों में धनबल के बढी प्रयोग और उधर धन को एकत्रित करने के लिए राजनीतिक दलों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले नीतिगत समझौते से ही भारत और भारतीयों दोनों का भविष्य प्रभावित होने लगे और मुद्दी भर अभिजात्य लोगों की चांदी हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। ये बातें मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि इस बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो तु-तू, मैं-मैं होती रहती है, उससे अक्सर संशय पैदा होती है। चूंकि इस आन्धराधानी सियासी प्रवृत्ति को रोकने में हमारी उच्च पथस्थ कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों विफल रही है, इनके विशेषण में मीडिया की भूमिका भी पश्चात्ताप और अभिजात्य वर्गीय हितों की संरक्षक प्रतीत हुई है, इसलिए इन तमाम मामलों की निष्पक्ष जांच और अपेक्षित सनतामूलक कार्रवाई के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और स्थिल संसाइटी के प्रबुद्ध, उच्च योग्यतावासी, समाजसेवा में अनुभवी और वैचारिक सक्षम रखने वाले व्यक्तियों की एक जिम्मेदार चतंत्र एजेंसी बनाने योग्य और इनके प्राप्त निष्कर्षों पर जम्मात खरीबण करार जाने की जरूरत है, ताकि भारतीय संसद द्वारा जनविरोधी राष्ट्रवाद, हिंसा और जनविरोधी कानूनों की समीक्षा सभ्य—सभ्य पर की जा सके।

ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि बहुमत के जुगाड़ में राजनीतिक दल जो कुछ भी फंसले लिए गए हैं या लिए जाते हैं, या लिए जाने वाले हैं उससे साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। लिहाजा, सभ्य समाज के निर्माण में इनकी भूमिका भी पश्चात्ताप प्रतीत होती आई है। वहीं, हमारी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत से विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और स्वाार्थ परक पेशेवर या सामाजिक—आर्थिक दबाव समूहों के लिए जातों के लिए भारतीय समाज हित में नुकसान बनाए गए हैं, उससे आम भारतीय यानी आम आदमी के दूरगामी हितों पर कुदाराघात पहुंचा है। इसलिए जनहित के विरोध में जो फंसले लिए गए हैं, तत्सम्यक्भी कानून बनाए गए हैं, उन्हें बदलवाने में भी उपरुक्त एजेंसी की भूमिका को साथेंक बनने की दकार है। इन बातों को समझने—समझाने के लिए यहां पर एक दबावप्रस्तुत कर रहा हूं। मसलन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 20 फरवरी को कहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भारत में किसी और को सत्ता में लाना चाहते थे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ डॉलर अर्थात् अर्धवर्तित करोड़ के बाइडन प्रशासन के फंसले पर सवाल उठाया। लिहाजा, इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस पुनः आगने—तागने आ गई हैं। दूरअसलत, इस पुनः गुरुवार को मिथामी में एफआईआई प्राथमिकता विशेष समेकन में ये दिष्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाइडन प्रशासन भारत में किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहा था। हमें भारत सरकार को बताना होगा। हैरतअंगत है कि कांग्रेस के

पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर विदेश दौरे पर जाकर सार्वजनिक तौर पर भारत के लोकतंत्र में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की मांग करते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फंडिंग की पुष्टि कर उनको मिल रही मदद पर मुहर लगा दी है। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए बारिश भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ट्रंप को कोट करते हुए कहा कि हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत है। उनका बयान एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दस्ता विज्ञान (डीओजीई) द्वारा खुलासा करने के बाद आया है। वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि घुसपै एड से जुड़े ट्रंप के दावे बेवकूफ हैं। इस पर केंद्र खेत पत्र जारी करें, जिसमें दशकों से यूएसएड की ओर से सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को दिए गए संरक्षण का विस्तृत विवरण हो।

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर देने की क्या जरूरत है, पर एशिया अच्चा कर रहा है। ये सिर्फ कुछ फंडिंग हैं। सह सूची बहुत ही लंबी है। ऐसे में यह आवश्यक है कि भारत सरकार अमेरिका से पूरी सूची तलब करे और भारत के लोगों को पूरी जानकारी दे। इस पूरे मामले में शामिल लोगों की भूमिका की निष्पक्ष पड़ताल भी होनी चाहिए। इस बारे में जम्मू—कश्मीर के मुख्यमंि एन अदुल्ला ने टीवी ही कहा है कि चुनाव आयोग को उन रिपोर्टों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिका ने भारत के चुनावों में

मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्च किए हैं।

यदि आप इस मुद्दे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मामला बहुत गम्भीर है। इससे हमारे लोकतंत्र पर सवाल पैदा होता कि क्या उसका रिपोर्ट कंट्रोल विकसित देशों के धनबल के पास है। शायद इसलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए प्रसाद ने कहा कि भारत में मतदान को प्रभावित करने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर आवंटित किए गए थे। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस का भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए विदेशी फंडिंग से संबंध है। भाजपा नेता ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि महात्मा गांधी की विरासत पर दावे करने वाली पार्टी द्वारा ऐसा किया जाना बेहद दुःखद और शर्मनाक है। प्रसाद ने भाजपा मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना करने के लिए ट्रंप की ताजा टिप्पणी और 2023 में ब्रिटेन में दिए गए राहुल गांधी के बयान के ऑडियो क्लिप चलाए।

अमेरिकी संसदीय कांग्रेस से जुड़े हालिया विवाद तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि इस पर केंद्र सरकार खतब खत पत्र लगा। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र से आग्रह किया कि इस संस्था द्वारा भारत के सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों को दिए गए सहयोग का विस्तृत ब्योरा देने हुए खत पत्र जाना किया जाना चाहिए। वहीं, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यूएसएड के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जा रहे दावे बेवकूफ हैं। फिर भी केंद्र को जल्द इस मामले में एक खत पत्र जारी करना चाहिए।

अब सारा सोंपिए कि वह कितनी गम्भीर बात है। यह तो महज एक बानगी है जिसके सबूत भारत सरकार ने नहीं बहलें अमेरिकी सरकार ने दिए हैं। वहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच सत्ता में रहते हुए हस्ताक्षरित एमआरजे में शामिल विषयों के बारे में जानकारी अक्सर कांग्रेस से सवाल पृथ्वी आई है। वहीं, अपने देश के कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के अरब

कनेक्शन, वामपंथी पार्टियों के रूसी—चीनी कनेक्शन, समाजवादी दलों के यूरोपीय कनेक्शन आदि पर समय समय पर सवाल उठते आए हैं।

इससे साफ है कि भारतीय संसद द्वारा देश में लागू नई आर्थिक नीतियों के आलोक में और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो कतिपय जनविरोधी कानून बनाए गए हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि इन कानूनों के लागू होने के बाद जहां पूंजीपतियों की मनमानी बढ़ी है, वहीं आम नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की पेशेवर दुश्चराियां भी।

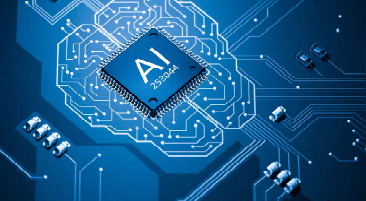
जरा गौर कीजिए, किसानों—मजदूरों—कारिगरो से जुड़े पुराने व नए कानूनों पर, नौकरी—पेशा लोगों से जुड़े पुराने और नए कानूनों पर, विभिन्न उद्यमों से जुड़े पुराने और नए कानूनों पर, राष्ट्रीय संरक्षक ानों के उपयोग से जुड़े पुराने और नए कानूनों पर, सरकारी और निजी कम्पनियों से जुड़े पुराने व नए कानूनों पर, तफ्करा आपकों स्पष्ट नजर आएगा। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कानूनी आयातों सुसंग्रहियों आदि से जुड़े विभिन्न विषयों पर जो कभी कीजिए तो साफ महसूस होगा कि जहां इहानी कीर्तन अभ्याषिात रूप से बढ़ी है, वहीं इनकी गुलामता हीन सेवाओं, स्वायत्ततापूर्ण पद्धतों की जनहिहिी मोतिरिाति करने वाला महज खाना पूर्ति कर रहा है।

वहीं, इन मुद्दों पर न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया की चुप्पी भी हैरतअंगेज है। शायद लोकपाल के गठन में भी ऐसे ही लोग बचाक हैं। खुद के संप्रदाय के मुख प्रचारकों और राष्ट्रीय संरक्षक अरविह केररीवाल भी जबकि मुख्यमंत्री रहे, लोकपाल की नियुक्ति को अपने विचारक समझे। जबकि ऐसे ही साजिश—भाजपा की सोच की ये सांयुजिनिात निद करते आए हैं। वहीं, अक्सर आख्यान और साम्प्रदायिकता पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों का उपरोक्त विभिन्न मुद्दों पर अजाना बन रहे रहना यह दर्शाता है।

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं

ए.आई. वर्चस्व के लिए वैश्विक संघर्ष

—मनीष तिवारी—



घंटी ए.आई. के क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत का संकेत है।

दक्षिण कोरिया और इसराईल जैसे छोटे देश हाईटेक, साइबर सुरक्षा और तैय्य अनुयोगों पर ६ यान केंद्रित करते हुए अपने स्वयं के ए.आई. क्षेत्र बना रहे हैं। हालांकि, वैश्विक ए.आई. शासन खंडित बना हुआ है, जेसा कि पैरिस ए.आई. शिखर सम्मेलन 2023 में अमरीका और यू.के. जैसे प्रमुख खिलालियों के दृष्टिकोण में अंतर और विरोध ाभास से स्पष्ट होता है।

खोए अवसरों की कहानी रूपनने मजबूत उदाहरण हैं। क्षेत्र के बावजूद, भारत में स्पष्ट और प्रभावी ए.आई. रणनीतिक का अभाव है। भारत में ए.आई. मिशन जैसी सरकारी पहल ने अला है और कोई खास प्रभाव नहीं डाला है। ए.आई. अनुसंधान और विकास में निवेश अपर्याप्त है। जुलाई 2024 में पेश किए गए भारत के आध्यक्ष संरक्षण के अनुसार, भारत अपने सफल परेवृ उत्पन्न का केवल 0.64 प्रतिशत है, जो चीन के 2.41 प्रतिशत के बाद दूसरा है। ए.आई. अनुसंधान और इसराईल तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों द्वारा खर्च किए जाने वाले 4-5 प्रतिशत से काफी कम है। भारत ने ए.आई. मिशन के लिए बजट 2024-25 में ६51.75 करोड़ से घटकर 173 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि 2025-26 के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट अनुमान है। जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक स्तर से अभी भी काफी कम है।

चेंज इंजन की एक रिपोर्टों में भारत को ए.आई. अनुसंधान योगदान में 14वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक योगदान का सिर्फ 1.4 प्रतिशत है, जबकि यू.एस. और चीन क्रमशः 30.4 प्रतिशत और 22.8 प्रतिशत योगदान के साथ सबसे आगे हैं। इस बीच, हांगकांग, सिंगापुर और महलपुरा जैसी छोटे देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस अंतर को पाटने के लिए, भारत को आगामी 5 वर्षों में अपने ए.आई. अनुसं्र 10 घण्टाओं को कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ बढ़ाना चाहिए। भारत की ए.आई. महाकथाका बुनियादी ढांचे की कमी से बाधित व एक समग्र ए.आई. परियोजनाकी तन एक मजबूत सीमीकडवरे और कम्प्यूटिंग उद्योग पर निर्भर करता है।

—राकेश कुमार आर्य —

यदि हम इस मामले पर सतर्क रहित वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा है कि सारा संसार इस समय एक अघोषित युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है। आतंकवाद के नाम पर एक र्गव के लोग निर्दोष लोगों का खून बहाना और अपना मजबूती विस्तार करना अपनी विरासत का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। वास्तव में निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर उन लोगों के जिंस प्रकाश बना विस्तार किया है, वह उनके लिए इस समय एक मार्गदर्शक अनुभव है। उस अनुभव की छिछली कई शताब्दियों से शेष संसार के लोग आलोचना करते आ रहे हैं। परंतु उन पर इस प्रकार की आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे विपरीत ये लोग इस प्रकार का विमर्श बनाने में भी सफल रहते हैं कि आतंकवाद भावा मुद्दी भर लोगों की सोच है। इस्लाम का आतंकवाद से दूर—पूर भी सवंे 1 नहीं है। इस दुष्प्रचार के लिए उनके पास एक पूरी कौशल होता है, जो केवल इसी मोर्चे पर लड़ती है कि आतंकवाद को इस्लाम के साथ न जोड़ा जाए।

अली शिना अपनी पुस्तक ‘अंडरस्टैंडिंग मुहम्मद और मुस्लिम’ में लिखते हैं कि 11 सितंबर सन 2001 के बाद 13 वर्षों में 24300 अमेरिकी हमले हुए। परिणाम स्वरूप पूरे संसार में सैकड़ों हज़ारों नागरिकों की मृत्यु हुई और चोट पहुंची। औसतन प्रतिदिन पांच आतंकी हमले हुए। आक्रमणकारी अपराधकों कोई दैत्य नहीं थे, अपितु मुस्लिम थे। अपने मजहब में उनका विश्वास था और उसके अनुसार ही उन्होंने यह काम किया। ऐसी ही सोच वाले दसियां करोड़ अरब भी हैं, जो वह सब भी वही करने के लिए तैयार बैठे



है। वह लिखते हैं कि इस्लाम अपनी सफलता के लिए आतंकवाद का ही रास्ता है।

विद्वान लेखक की इस बात में बहुत ही बल है कि ‘ इस्लाम आतंकवाद का ऋणी है।’ आज जितने भी वही देशों में इस्लाम का प्रभाव लहरा रहा है, वहां कभी सनतनी हिंदुओं का वर्चस्व था। ई-थीर-सीरे सनतन के लोगों में जड़ता ने प्रवेश किया और कई र्थानों पर दोहाड़े की बजाए चौराहे पर आते चले गए। उनकी किफतव्यविभूत की स्थिति का भी इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों ने कहीं लड़ाई से तो कहीं थपाने से, कहीं बहला फुलाने तक तो कहीं लातच देकर उनमें से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस्लाम ने आतंकवाद के माध्यम से लोग का भयादीहन करने की अपना विस्तार किया है। उन तथ्य योचनोविरा सक्षमों को ब्याव कर रहे हों, तब भी कुछ लोग यदि यह ना कहें कि इस्लाम और आतंकवाद का मौलौ दामन का साथ है तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पर तरस ही आता है।

अली साहब हमें बताते हैं कि मदीना में अपना कर्म रखने के साथ ही मोहम्मद ने अपने आतंक का अभिमान आरंभ कर दिया था, तब से उनके अनुयाई भी वही करते

चले आ रहे हैं। भारतीय मायत्ता में किसी पर घात लाकर हमला करना नैतिकता और मानसता के विरुद्ध है, जबकि इस्लाम इसे जायज मानता है। वीरता में है कि शत्रुपक्ष व्यक्ति से ही युद्ध किया जाए। इतना ही नहीं, जिस पर जाला हरियाएर है वसा ही हरियाएर जाला व्यक्ति उससे युद्ध करे। जब 10 वर्ष में 24300 आतंकी हमलों का एक कीर्तिमान एक र्गव विरोध के लोगों के नाम अंकित हो और प्रतिदिन पांच आतंकी हमले संसार में हो रहे हों, तब विश्व शांति की बात करना कितना उचित हो सकता है?— यह सच ही अनुमान लगाना जा सकता है। यह तथ्य और भी अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग प्रतिदिन की पांच आतंकवादी घटनाओं को लगभग जीवन का एक अनिवार्य अंग मान चुके हैं। तभी तो इतने निर्भम अत्याचारों पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा को पूर्व निषाजित योचना के अंगरंग इस प्रकार विधायितरित दिए जाते हैं कि आतंकवादी को कोई मजबूत नहीं होता और आतंकवाद इस्लाम की मूल बहानी के अप्रतिद्व है। टीओबी वैनलों पर या समानार पत्रों में इस विषय में जो भी चर्चाएं होती हैं, उनके कतिपय ही लोग आतंक इस्तीफा करने के विमर्श के इर्द-ओ-इर्द धूमते लेख लिखते हुए या चर्चा करते हुए मिल जायेंगे।

गोड़धोइया नाले में मिट्टी के नीचे दबने से दो मजदूर की मौत



संवाददाता-गोरखपुर। गुरिलहा थांना क्षेत्र के सेमरा नम्बर दो के पास स्थित गोड़धोइया नाले के खुदाई के दौरान अंडर ग्राउंड केविल कट गइ थी, जिसको जोड़ने के लिए दो मजदूर लगभग 25 फिट गड्ढे में जाकर तार जोड़ रहे थे। उसी समय नाले के किनारे के मिट्टी के ढेर के नीचे दबकर मौत हो

7: 25 फिट गड्ढे में जियो फाइबर का तार जोड़ रहे थे। उसी समय मिट्टी का ढेर दोनों मजदूरों पर गिर गया।

फ़ाइनर फानन में दोनों घायलों को मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मनोरमा यादव को सहकमी एम्स लेकर चले गए, जहां डॉक्टरों ने मनोरमा को भी मृत घोषित कर दिया।

रात 12 बजे गुरिलहा पुलिस को सूचना मिली तो रात में एम्स जाकर गृह में खूबा दिया गया। परिवार को आसुरे है कि जियो फाइबर कम्पनी का कोई सुपरवाइजर या जिम्मेदार वहां उपस्थित नहीं था। मजदूरों को मिट्टी के ढेर के नीचे कारन करने के लिए भेज दिए यह पूर्ण रूप से लापरवाही है।

बड़े बकायेदारों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर छापा

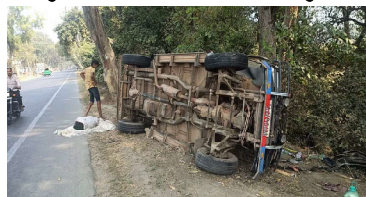


संवाददाता-अयोध्या। अयोध्या नगर निगम ने हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसा जाऊ कर दिया है। जिन बड़े बकायेदारों ने टैक्स नहीं जमा किया है उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर निगम की टीम ने रिसावागंज स्थित शहर के जाने-माने अलका राज होटल व अलका टावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा। सहायक नगर आयुक्त ने टीम के साथ छापा मार्कर प्रॉपर्टी अटैच करने की चेतावनी दी। अलका राज होटल व अलका टावर पर

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। जोगिया कोतवाली क्षेत्र के नीग-बांसी मार्ग पर सप्ता चौहाल के पास रविवार की देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र के सुभाषाट गांव निवासी मजनु उर्फ अखिलेश (23) पुत्र सुरेंद्र व दिनेश (24)पुत्र सर्वजीत रविवार की शाम बाइक से जोगिया में मोबाइल नवनाथ आए थे। मोबाइल नवनाथ के बाद देर रात वापस घर आ रहे थे। अभी वह सप्ता चौहाल के पास पहुंचे ही थे कि किसी वाहन ने उन्हें रैद दिया। इस दौरान आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जांच जारी है। मृतकों की परिवारीजनों में कोहराम मच गया। जोगिया कोतवाली प्रमोनी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

राम मंदिर के दर्शन करके प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन टकराया, 10 श्रद्धालु घायल



संवाददाता-अयोध्या। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर वापस प्रयागराज लौट रहे तेलंगाणा के 10 श्रद्धालु सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। श्रद्धालुओं का वाहन एक कार से आगे-आगे टकराते कर के बाद पलट गया। श्रद्धालुओं के वाहन में 12 श्रद्धालु सवार थे। इसमें 10 श्रद्धालु घायल हुए। पांच को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जबकि पांच श्रद्धालु का ओपीडी में ही इलाज करवाया गया। हादसा थाणा पुराकलंदर के रोडवेज बसस्थान के पास प्रयागराज हाईवे पर हुआ। बताया गया कि सभी श्रद्धालुओं ने काशी विध्वनाथ

का दर्शन कर प्रयागराज में महाकुंभ स्नान किया। इसके बाद से अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया। दसम पूजन के बाद सभी 12 श्रद्धालु वापस प्रयागराज लौट रहे थे तभी प्रयागराज हाईवे पर थाणा पुराकलंदर के रोडवेज बसस्थान के पास सामने से आ रही कार से टकराव के बाद दोनों वाहन पलट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां पर उनका उपचार किया गया। कार सवार दो अन्य लोग भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं।

अपने ही घर से नहीं निकल पा रहे लोग-सपा



संवाददाता-अयोध्या। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर अयोध्या लोगों को दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन की बंदिशें अयोध्या धाम के स्थानीय लोगों पर भारी पड़ रही हैं। एक तरफ महापौर निरंजना पति बिंदीया ने जिला प्रशासन से वार्ता कर बंदिशों को कम करने का प्रयास किया है तो वहीं, सोमवार को समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को जारि होर से उठाया है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन लिखि मजिस्ट्रेट को सौंपा। पवन ने कहा कि धूम के दौरान अयोध्या में भारी भीड़ आ रही है तो श्रद्धालुओं को भी सुगमयावक जिला प्रशासन दर्शन

आमी नदी पर पक्का पुल निर्माण, कसिहार में कट खोलने की मांग

संवाददाता-गोरखपुर। किसान कौशल समेदी प्रदेश सोचिव अविनारा पति त्रिपाठी और जिला अख्यक्ष हरिसेकत त्रिपाठी ने सोमवार को मण्डलाध्यापक अमिल दींगरा के कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सोमगौरा के पास आमी नदी पर पक्का पुल और पनचूच 24 पर कसिहार के पास कट खोलने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि गंगाधारा गांव में कई किसानों की जमीनें आमी नदी के दूसरी तरफ हैं। आने-जाने के लिए किसान बांस-बल्ली के पुल का इस्तेमाल करते हैं। यह बारिश के दिनों में काफी जोखिम भरा होता है। इसके अलावा बताया कि पनचूच 24 से गंतय के लिए कोई समुचित कट न होने से जनता परेशान है। कसिहार, मलाव, भूमगावा गांव में किसानों की खेती ताल में है। बैरिकेडिंग के कारण किसानों को डेड से दो किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। इस दौरान बिनीत पाण्डेय, संजय उर्फ लारा आदि मौजूद रहे।

28 फरवरी को होगी सरकारी गन्ना विभाजक समिति की बैठक

संवाददाता-संतकबीरनगर। सरकारी गन्ना विभाजक समिति खलीलाबाद में आगामी 28 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी। ग्प चेयरमैन के साथ सभी डायरेक्टर भी शिरकत करेंगे। आमोचित बैठक में पुरानी कार्रवाईयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सरकारी गन्ना विभाजक परिसर में जाकर भवनों की बर्रमात के लिए गन्ना विभाजक परिषद से अग्रिम धन लेकर उधर लिए गए उरने के लिए भी चर्चा की जाएगी। परिसर का बाउंड्रीवाल का निर्माण करने के लिए विभाजक व सांत्व निधि से परस्पर लेने पर भी चर्चा होगी। सरकारी कारी मिला हो गया है। इसकी वजह से बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। उधर परिसर में जेडि निरवाने के लिए भी बैठक में मंमन किया जाएगा। समिति के कर्मचारियों को छठ वसंत मान दिए जाने पर चर्चा होगी। समिति के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों के निवासियों को आसुरे कर और ठेकानों का निर्माण व आसुरे भी किया जाएगा। इस पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण के साथ चुनना व्यय की संवर्धित और रक्कतों पर भी विचार किया जाएगा।

जिले में हैं 113 केंद्र, बोर्ड परीक्षाएं शुरू, डीएम ने किया निरीक्षण

संवाददाता-संतकबीरनगर। एक दिन पहले ही डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने परीक्षा ड्युटी में लगे अधिकारियों को सचेत किया था कि अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका भीतिक सत्यापन करने और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की जांच करने परीक्षा शुरू होते ही डीएम महेंद्र सिंह तंवर खुद पहुंच गए ध्यनिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। परीक्षा की सुविधा और निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एमपी सच्यजीत गुप्ता ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा के लिए जिले में 113 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुल 55,388 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं।

एक दिन पहले ही डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने परीक्षा ड्युटी में लगे अधिकारियों को सचेत किया था कि अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसका भीतिक सत्यापन करने और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की जांच करने परीक्षा शुरू होते ही डीएम खुद पहुंच गए। साथ में एमपी भी थे। सोमवार को मूठी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर मीडिएट की परीक्षा दो पाठियों में आयोजित होगी। इसके लिए सभी 113 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रश्न पत्र तीन दिन पूर्व ही केंद्रों पर पहुंचा दिए गए थे। जो डबल लोक में रखे गए हैं। परीक्षा



शुरू होने से एक घंटे पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसे खोला जाएगा। वह भी सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा।

बेटे के पास गए थे लखनऊ, चोरों ने मकान खाला

संवाददाता-गोरखपुर। शाहपुर इलाके के असुर स्थित भेडिगाड़ में एक सप्ताह से बंद मकान का ताला तोड़कर चोर नानदी सहित लाखों के नकद समेत चोर करत हो गए। पड़ोसी की सूचना पर रविवार को लखनऊ से वापस पहुंचे भिडेल ने पुलिस को सूचना दी। शाहपुर पुलिस रविवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

खई ट्रक से कार टकराई चार घायल जिला अस्पताल रेफर

संवाददाता-गोरखपुर। गंगाध क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोरखिया मोड़ पर खई ट्रक से सोमवार को नौ हाइस्कूल से लौट रही एक कार टकरा गई। हादसे में गोरखपुर फर्टिलाइजर इलाके के रहने वाले कार सवार सूर्यभ (61), धर्मन कुमार (40), सोनू चौधरी (40) और अशोक (5) घायल हो गए। दहलने निकले लोगों ने घायलों को पुलिस के मदद से स्वास्थ्य केंद्र गंगाहा पहुंचाया। जहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

आदालती नोटिस
(हेतु सन्दर्भित करने की सूचना साधारण प्रकरण)
आदेश 5 कायदा 3)
न्यायालय-श्रीमान प्रथम अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला-बस्ती
सिविल अपील 41 / 2024
ज्ञानमती देवी
रामा
रामा
1/2 दिनेश 1/3 गनेश 1/4 लाल चन्द्र पुनगुण स्वो रामहित 2। मिर्झालाल पुत्र गंगाराम 3. जय प्रकाश गुप्ता पुत्र रामहित गुप्ता
-रसनादेव प्रथम वर्ग
4. दुर्गा प्रसाद पुत्र राम अचल साकिमान मौजा खलीली कला तथा रूखीली परगना महानर पश्चिम तालिका खलीली जिला-बस्ती
तारीख पेशी 24-03-2025
बुकि उपरीभांगिकात ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएव आगे एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 03 के 24 दिनांक को 10.00 बजे पूर्वान्न में स्वयं या समर्पक रूपम अनुमिष्ट अनिवार्य अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होएं एसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जावेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिनांक को निकाली गयी।
दो हाकिम

स्वास्थ्य केंद्रों पर बने वार रूम का नोडल अधिकारी करेंगे निरीक्षण

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के सभी केंद्रों पर वार रूम बनाया गया है। अब यह सभी वार रूम नोडल अधिकारी की निगरानी में होंगे। इसके लिए सीएमओ ने आठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर वार रूम के निरीक्षण का जिम्मा सौंपा है। अब अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक दिन निरीक्षण कर व्यवस्था को देखेंगे। इसके बाद रिपोर्ट सीएमओ को सौंपेंगे। दखलान, डीएम डॉ. राजा गणपति आर के निदेश पर नवंबर 2024 में जनपद के मेडिकल कॉलेज व समस्त ब्लॉक स्तरीय सीएचसी-पीएचसी पर डेडिकेटेड वार रूम बनाया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस वार रूम के माध्यम से सातवें, आठवें व नौवें माह वाली गर्भवती, समस्त हाई रिस्क प्रेग्नेसी (एचआरपी) व ई-रूपी बाउंडर वाली गर्भवती का फॉलोअप कर संस्थागत प्रसव सीजेरियन प्रसव के संदर्भ में जानकारी देना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा लामार्गी हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जल समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना है। इस कार्य को वार रूम में रोजर वार

तैनात कर्मचारी कर रही है। डीएम ने वार रूम का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसमें आठ नोडल अधिकारियों को जिम्मा सौंप कर निर्देशित किया गया है कि सप्ताह में कम से कम एक बार आवंटित ब्लॉकों के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वार रूम, एनपीएसयू प्रसव कक्ष व ओटी का निरीक्षण कर सीएमओ को सौंपें। सीएमओ ने सीएमएस डॉ. एके झा को मेडिकल कॉलेज, डिप्टी सीएमओ डॉ. आजी सिंह को डूधना-खुनियाँगंज, डॉ. एमएम त्रिपाठी को झुमरियागंज-नवगपुर, डॉ. वीएन चतुर्वेदी को शोहरतगढ़-बदनी, डॉ. शेखमान को खेरखुआ-बसंतपुर (बाँसी), डॉ. संजय गुप्ता को नौगढ़-उरका बाजार, डॉ. आशीष अग्रवर्मा को बर्दौली-लोटन व नोडल अधिकारी पीपीएमजीपीडी सौंपने का निर्देश दिया गया है।

शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। बांसी कर्ये के आजादनगर वाई में एक किएर के मकान में रह रहे शिक्षक के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का नुकसान

आदालती नोटिस
सम्मान वारसे कारवायव उम्हू तनकीहत तबल
(आदेश 5 कायदा 1 व 5)
मूववाद पेश 549 / 2021
न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ)खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती
मन्जु यादव
बनाम
दिनेश कुमार आदि
1. दिनेश कुमार उमर लगभग 25 वर्ष पुत्र मोहना लाल 2. लालजी उमर लगभग 45 वर्ष पुत्र राम मुकुंद 3. श्रीमती सुनीता उमर लगभग 46 वर्ष पत्नी ओम प्रकाश निवासीगण ग्राम फूलपुर तथा कलवारी परगना नगर पुरव तहसील व जिला-बस्ती
तारीख पेशी 29-04-2025
हरगहा न ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आज आदेश 29 माह 04 सन 2025 ई० बारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करन वकई वकिके किया गया हो और जो कुल उम्हू उम्हू मुतुलिका मुकदमा जबाब दे सकें या जिसके साथ कोई और सख्त हो जो कि जबाब ऐसे सवागत का दे सकें तबखिर और हरगहा वही तारीख जो कीजये इजहार के लिये मुकदर है वारसे इम्नोसिल कारई मुकदमा के तबवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोजे जुमना दरखोज को जिनको आप अन्या जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं पेश करें। आपको इस्तिना दी जाती है कि अगर बारह मजकूर आप हाजिर न होगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपका मससुआ और फैसला होगा। बसखत मे दरस्तल और मुहर आसुर के आज तबवीबी माह सन 20 ई० जारी किया गया।
दो हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संवाददाता-गोरखपुर। प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि०. एन० हाल 1-4 A लोहिया कांमलेखा जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (पं०प०) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक स्वो दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह
संयोजक सम्पादक-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष-मंजीबाब कर्णाल-य
युक्तीमर्द परिसर लक्ष्म घाट
अयोध्या-कैलाश
लक्ष्मण कार्यालय-
आसुरा नाला, एल०ई० कालीनी,
लेखर एक कानपुर रेल लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय-
इन्डोभाग गोरखपुर।
मो०9450567450 9336715406,
ई०बि०bhartiastbasi@yahoo.com
bhartiastbasi@gmail.com